

प्रेषक,

यू.सी.एन.सी.

सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श,

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महाप्रशासक,

उत्तरांचल,

233/5, नया बाजार,

राजौली, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 1

विषय: महाप्रशासक कार्यालय हेतु सुजित पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।
देहरादून : दिनांक : १५ फरवरी, 2006

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 20-एक(7)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2005, दिनांक 9.5.2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाप्रशासक कार्यालय हेतु शासनादेश संख्या 15-एक(1)/न्याय अनुभाग/2003, दिनांक 14.2.2003 द्वारा सुजित सभी अस्थायी पदों के कार्यालय को वर्तमान शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1.3.2006 से 28.2.2007 तक बढ़ाये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-04 के लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजन-800-अन्य व्यय-07-महाप्रशासक कार्यालय, नैनीताल-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामों द्वारा जायेगा ।

भवदीय,

(यू.सी.एन.सी.)

सचिव ।

संख्या : 2-एक(7)/XXXXVI(1)/2006-582/01-तद्विनोक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों) उत्तरांचल, मजरा, देहरादून ।

2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।

3. विल अनुभाग-5/एन.आई.सी./गार्ड फाइल ।

आशा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)

अनुसन्धिव ।